LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 29, 1976/Chaitra 9, 1898 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: I have to inform the House of the said demise of one of our former colleagues, Shri Kalika Singh, who passed away at Azamgarh on the 16th March, 1976 at the age of 65.

Shri Kalika Singh was a Member of Second Lok Sabha during the years 1957-62 representing Azamgarh constituency of Uttar Pradesh. Earlier he had been a Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly during the years 1952—56. An eminent lawyer and a journalist, he had edited a number of Hindi journals. He was a prominent leader in his student days and led the UP students' agitation for freedom in 1942. He also took keen interest in the development of Eastern UP and worked for the upliftment of the depressed classes in his home State :

We deeply mourn the loss of this friend, and I am sure, the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

(The Members then stood in silence for a short while)

बिहार को सिंचाई के लिए जल की पूर्ति

*281. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम से किन किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया जाता है ;

(ख) उससे बंगाल तथा बिहार में कितनी भूमि सींची जाती है ।

(ग) क्या बिहार को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान, हुगली, बंकुरा और हावड़ा जिलों को दामोदर घाटी निगम प्रणाली से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया गया है ।

(ख) इस समय पश्चिम बंगाल में लगभग 5.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को दिया जा रहा है । बिहार में दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं से इस समय कोई सिंचाई नहीं हो रही है ।

(ग) और (घ). बिहार सरकार दामोदर घाटी निगम के तिलैया जलाशय के जल का गया जिले में लगभग 48,000

हैक्टेयर में खरीफ के दौरान सिंचाई की व्यवस्था के लिए तथा हजारी बाग जिले में लगभग 69,000 हैक्टेयर में दामोदर घाटी निगम के कोनार जलाशय के जल का सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव रखती है।

बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर समझौते पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार में सिंचाई के लिए तिलैया एवं कोनार जलाशयों के पानी का समुपयोजन करना शामिल है, इस समय दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने विवरण को ध्यान से पढ़ा है। पिछले चार-पांच वर्षों से जब से मैं संसद् सदस्य चुन कर आया हूं, करीब-करीब इसी तरह से उत्तर मिल रहा है इस उत्तर में कोई अन्तर नहीं आया है।

जो विवरण इस समय सभा पटल पर रखा गया है, मैं उस का कुछ भाग पढ़ कर सुना रहा हूं—"बिहार में सिंचाई के लिए तिलैया एवं कोनार जलाशयों के पानी का समुपयोजन करना शामिल है, इस समय दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।" चार-पांच वर्षों से हम को यही उत्तर मिल रहा है कि विचार-विमर्श किया जा रहा है। राज्य सरकारों के अफसरों के टी० ए० और डी० ए० पर अब तक इतना खर्च हो गया होगा, कि उस से एक पूरी योजना ही बन जाती। यह तो एक सौभाग्य की बात है कि एक साल के लिये हम लोगों का टर्म बढ़ गया है, वरना हम कैसे वहां जा कर मुंह दिखलाते। यह मेरे अपने क्षेत्र का मामला है—इसलिये मैं आप के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि डी० वी० सी० के तलैया और कोनार दोनों परियोजनाओं से बिहार की सिंचाई के लिए पानी मिल—यह विषय कब से सरकार के पास विचाराधीन है और कब तक यह फाइनल हो जाएगा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अभी हाल में प्रधान मंत्री जी तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री जी की उपस्थिति में बिहार तथा बंगाल के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में हुई थी? यदि हुई थी तो उस में कौन सी बातें तय की गई?

श्री केदार नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, डी० वी० सी० की ये योजनायें बाढ़ को रोकने के लिये, सिंचाई योजनाओं के लिये और विद्युत् के लिए बनाई गई थीं। जहां तक बिहार की सिंचाई का सवाल है—यह बात सही है कि यहां से बिहार में बिल्कुल सिंचाई नहीं होती है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी कुछ अनिच्छा व्यक्त की थी, कि उस को सिंचाई के लिये आवश्यकता नहीं है . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : उन की अनिच्छा थी, क्या आप कोई इस का प्रमाण दे सकते हैं उन्होंने अपनी अनिच्छा कैसे व्यक्त की थी? क्या कोई राज्य सरकार कह सकती है कि उसे जरूरत नहीं है?

श्री केदार नाथ सिंह : यह रिकार्ड पर है और यह सही बात थी। उस के बाद 1973 में यह बात फिर शुरू हुई कि बिहार को सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता है। 1973 के बाद दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और यह तय हुआ कि दोनों सरकारों के अधिकारी बैठ कर मामले को तय करें। गत मार्च के पहले हफ्ते में यह मामला तय होने को था कि बीच में डी० वी० सी० आ गया, इसलिए कुछ समय के लिए यह मामला फिर रुक गया।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है। मैं इस में आप की महानुभूति चाहता हूं—मैंने ठोस सवाल पूछा था कि यह कब फाइनल होगा और क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय कृषि मंत्री जी की उपस्थिति

में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या बात तय हुई ?

श्री केदार नाथ सिंह . मैंने बतलाया है—मार्च के पहले हफ्ते में मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी । जहां तक प्रधान मंत्री जी और सिंचाई तथा वित्त मंत्री जी की उपस्थिति का सवाल है, इस की सूचना हमें नहीं है । लेकिन यह बात सही है कि दोनों राज्य मंत्रियों की बैठक हुई थी और करीब-करीब मामला तय होने को है । थोड़े दिन इन्तजार करें, यह मामला तय हो जायेगा ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोनार और तिलैया इन दोनों योजनाओं की प्रारम्भिक रूप रेखा बन चुकी है ? यदि हां तो इन दोनों स्कीमों पर कितना पैसा व्यय होगा और इस में केन्द्रीय सरकार कितना देगी और राज्य सरकार कितना व्यय करेगी ?

श्री केदार नाथ सिंह दोनों योजनायें करीब करीब तैयार हो चुकी है । लेकिन दोनों प्रान्तीय सरकारों के क्लीयरेंस के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लीयर कर देगी । जहां तक पैसे का सवाल है चूंकि सिंचाई योजनायें प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्र में आती हैं इसलिये दोनों योजनाओं में तिलैया में 14 76 करोड और कोनार में 11 करोड रु० व्यय होगा, और 1976-77 की योजना में 1 करोड रु० दोनों के लिए मंजूर कर दिया गया है ।

श्री नवल किशोर सिंह . डी० वी० सी० के निर्माण में बिहार को और बिहार की जनता के एक बड़े हिस्से को बड़ा त्याग करना पड़ा है । जिस समय डी० वी० सी० बनी थी उस समय कल्पना यह थी कि बिहार में सिंचाई की कोई योजना नहीं बन सकती है इसलिये उस की बिजली बिहार को मिलेगी । लेकिन सिंचाई की योजना तो बंगाल में चली ही गई, सारी बिजली भी बंगाल में चली गई । हाल में मयूराक्षी डैम, जिस को कैनाडा डैम भी कहते हैं वहां दो सिंचाई योजनायें बनी एक तो बंगाल में बांकुरा (बर्दवान जिले) में और एक बिहार के संथाल परगना के लिये बनी । लेकिन बिहार की जो योजना बनी वह इतनी ऊंची जमीन पर कैनाल बनी कि उस से कोई सिंचाई 10 वर्ष में बिहार में नहीं हो सकी । अब बिहार सरकार ने 1973 के बाद यह दो योजनायें बनाई है । देश में पिछले दो सालों में प्रधान मंत्री की पहले से जितनी भी नदी घाटी योजनाओं के झगड़े थे दो प्रदेशों के बीच में वह हल हो चुके है । मेरा ख्याल है कि एक आध कोई बची हो तो हो । क्या सरकार ने इस नये परिवेश में कोई समय की रूपरेखा निश्चित करने का विचार किया है जिस के अन्दर डी० वी० सी० के पानी का बटवारा उचित रूप से बंगाल और बिहार के बीच में हो जाएगा और कोनार और तिलैया की जो स्कीमें सरकार ने तैयार की है उनको कार्यान्वित करने के लिये बिहार सरकार को अनुमति दे दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात का जवाब दीजिए । दूसरी का तो जवाब इन्होंने दे दिया है ।

श्री केदार नाथ सिंह : मयूराक्षी के बारे में दोनों सरकारों में बातें हो रही है । इसी समझौते में उसका भी हिस्सा होगा । और जहां तक समय का सवाल है इस के बारे में मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी सरकारों पर ज्यादा जोर डालें तो अच्छा होगा ।

SHRI INDRAJIT GUPTA As a matter of fact nobody grudges that any water from this D V C. Project should also be utilized for irrigation purpose in Bihar, and we all hope that an amicable settlement will be reached soon. I would like to draw the attention of the Minister to the last paragraph of his statement where he says "The agreement on various issues concerning the States

of Bihar and West Bengal, which, *inter alia*, includes utilisation of waters of the Tilaiya and Konar reservoirs for irrigation in Bihar, is at present under discussions. I would like to know from him whether this means—I am not clear about the meaning—that there are a large number of other issues also which are currently under consideration, and this particular question of water for irrigation purposes is to be part of some sort of a package settlement or package deal including other issues as well, and, if so, what are those other issues or is it that this particular issue is likely to be settled separately or independently or is it going to be some sort of a package agreement. The implication is not clear.

SHRI KEDAR NATH SINGH: There are certain other outstanding issues between the States of Bihar and West Bengal. All issues are under consideration. Besides Tilaiya and Konar reservoirs, there are some other projects, like, Ajaya river project in which both Bihar and West Bengal States are concerned. Then, there is the development project of Swarnarekha river in Bihar and Mayurakshi river project. There are some other projects for which acquisition of land is required. All these four or five issues are under consideration between the States Governments of Bihar and West Bengal.

MR. SPEAKER: Whether there is package programme? That is what the hon. Member wanted to know.

SHRI KEDAR NATH SINGH: We are trying to do it.

Construction of Quarters during 1976-77

*284. SHRI R. S. PANDEY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal before Government for construction of more quarters of Types I and II during 1976-77 for Government staff; and

(b) if so, broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI H.K.L. BHAGAT (a). Yes Sir.

(b) 696 type I and 1130 type II quarters are proposed to be taken up for construction during 1976-77.

SHRI R. S. PANDEY: Very good work is being done. Thank you very much.

SHRI S. R. DAMANI: There is an acute shortage of quarters in all metropolitan cities, like, Bombay, Calcutta and Madras. The officials who are transferred to these places find it very difficult to get accommodation. In view of this, may I know from the hon. Minister whether there is any programme of constructing more staff quarters in all these cities.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I have with me the information. There are programmes for the construction of staff quarters in different cities and some staff quarters have been constructed. I have with me even the percentages of satisfaction in all these cities. If the hon. Member wants, I can give the information to him.

MR. SPEAKER: You can send it to him.

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की जो हजारों दरखास्तें मकानों के वास्ते लगी हुई हैं, उन्हें मकान नहीं मिल रहे हैं, तो कब तक उन को मकान मिल जायेंगे ?

SHRI H. K. L. BHAGAT: I cannot say as to when every Government servant will be able to get a quarter. I have with me the percen-